
इकाई 15 भारतीय कृषि में पूँजी निर्माण

संरचना

- 15.0 उद्देश्य
- 15.1 प्रस्तावना
- 15.2 संकल्पनात्मक रूपरेखा
 - 15.2.1 पूँजी
 - 15.2.2 पूँजी निर्माण
 - 15.2.3 पूँजी और पूँजी निर्माण के प्रकार
 - 15.2.4 पूँजी निर्माण के स्रोत
- 15.3 पूँजी निर्माण के लिए लेखाकरण की प्रणाली
 - 15.3.1 कृषि में और कृषि के लिए पूँजी निर्माण
- 15.4 कृषि में पूँजी निर्माण की भूमिका
- 15.5 पूँजी निर्माण पर संस्थागत ऋण की सुलभता का प्रभाव
- 15.6 सकल पूँजी निर्माण में प्रवृत्तियाँ
 - 15.6.1 सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पूँजी निर्माण में हास के कारण
- 15.7 कृषि में निजी पूँजी निर्माण के निर्धारक तत्व
- 15.8 सारांश
- 15.9 शब्दावली
- 15.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें
- 15.11 बोध प्रश्नों के उत्तर/संकेत

15.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप :

- पूँजी और पूँजी निर्माण की अवधारणाओं के बीच अंतर कर सकेंगे;
- पूँजी और पूँजी निर्माण के भिन्न-भिन्न प्रकारों की परिभाषा कर सकेंगे;
- कृषि में पूँजी निर्माण के स्रोत बता सकेंगे;
- कृषि में पूँजी निर्माण की भूमिका स्पष्ट कर सकेंगे;
- कृषि में निजी और सार्वजनिक पूँजी निर्माण में प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर सकेंगे;
- कृषि में निजी और सार्वजनिक पूँजी निर्माण के बीच अनुपूरकता पर चर्चा कर सकेंगे;
- भारतीय कृषि में सार्वजनिक निवेश में हास के कारणों की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकेंगे; और
- कृषि में निजी पूँजी निर्माण के निर्धारकों का उल्लेख कर सकेंगे।

15.1 प्रस्तावना

किसी अर्थव्यवस्था या सेक्टर की संवृद्धि मुख्यतया तीन कारकों, अर्थात् जनांकिकीय संरचना में परिवर्तन (श्रम बल का विस्तार), पूँजी संचयन (भौतिक और मानवीय दोनों) और अभिनव प्रवर्तनों पर निर्भर करता है। इसलिए संवृद्धि/उत्पादन प्रक्रिया में पूँजी सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। वास्तविकता यह है कि हरित क्रांति के दौरान और हरित क्रांति के बाद की अवधि में कृषि में सार्वजनिक और निजी पूँजी निर्माण ने फार्म सेक्टर की प्रगति के लिए उल्लेखनीय योगदान किया। प्रारंभ में कृषि विकास मुख्यतः निम्न कार्यों में सार्वजनिक निवेश द्वारा संचालित होता था : (i) कृषि आधारभूत संरचना (जैसे विद्युत, सड़कें, सिंचाई और अनुसंधान तथा विकास (R&D)); (ii) विस्तार सेवाएँ; और (iii) बाजार और भंडारण सुविधाएँ आदि का विकास। बाद में ऐसे निवेशों द्वारा आधारभूत संरचना में सुधारों के कारण भूमि विकास, भौमजल सिंचाई, फार्म मशीनीकरण, आदि में किसान स्वयं भी निजी निवेश करने के लिए प्रेरित हुए। अभी हाल ही में निजी कंपनियों ने भी कृषि R&D, विस्तार, विपणन, संविदा कृषि और कृषि संबंधी अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है। इन निवेशों ने कृषि में सार्वजनिक निवेश को काफी अनुपूरित किया है।

उपर्युक्त रूपरेखा सुझाती है कि कृषि यद्यपि श्रम प्रधान कार्य है, परंतु इसे भी अपने विभिन्न कार्यों का दक्षतापूर्वक निष्पादन करने के लिए अचल पूँजी की और कार्यशील पूँजी की विशाल राशि की आवश्यकता होती है। विशेषकर, समय पर निवेश महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका ऋतुनिष्ठ कारकों जैसे वर्षा और मौसम परिवर्तन से गहरा नाता है। चूंकि बड़े और धनी किसानों को सामान्यतया पूँजीगत निवेशों की बेहतर सुलभता होती है और वे पैमाने की मितव्ययताओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं परंतु "छोटे और सीमांत", विशेषकर अल्पविकसित कृषि प्रदेशों में रहने वाले गरीब किसान पूँजी की संकटपूर्ण दुर्लभता का सामना करते हैं। इसके अलावा, जैसा कि अधिकांश मामलों में उनमें अचल परिसंपत्तियों में निवेश करने का सामर्थ्य भी नहीं होता है। इसे ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किया गया कोई भी निवेश उनकी छोटी आकार के स्वकर्षित जोतों और अल्प निवेश क्षमता को देखते हुए आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं हो पाता। इस जमीनी वास्तविकता को देखते हुए लगभग 80 प्रतिशत छोटे किसानों के लिए पूँजी कैसे हो, यह एक ऐसा मुख्य मुद्दा है जिस पर नीतिगत ध्यान देना आवश्यक है। इस पृष्ठभूमि पर वर्तमान इकाई का उद्देश्य भारतीय कृषि में पूँजी निर्माण से संबंधित विभिन्न पहलुओं की चर्चा करना है। अवधारणाओं की रूपरेखा के अलावा, हम पूँजी निर्माण की भूमिका, निजी पूँजी निर्माण के निर्धारकों, पूँजी निर्माण में प्रवृत्तियों, कृषि के लिए संस्थागत ऋण के प्रभाव का अध्ययन करेंगे।

15.2 संकल्पनात्मक रूपरेखा

शब्द "पूँजी" और "पूँजी निर्माण" के बीच अंतर है। साथ ही कुछ संबद्ध अवधारणाएँ भी हैं, जैसे अचल/कार्यशील पूँजी, सार्वजनिक/निजी पूँजी, निवेश, सकल/निवल पूँजी निर्माण, अचल पूँजी की खपत। पूँजी और पूँजी निर्माण पर आंकड़ों का निर्माण और उनके प्रयोग के लिए इन अवधारणाओं के बारे में स्पष्ट मत आवश्यक है।

15.2.1 पूँजी

शब्द पूँजी उन "परिसंपत्तियों" का संकेत देता है जो आगे माल और सेवा उत्पन्न करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में आदान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसलिए यह मुद्रा मात्र नहीं है बल्कि वह परिसंपत्ति है जिसके निर्माण के लिए मुद्रा और मानवीय प्रयास दोनों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार पूँजी की दूसरी विशेषता यह है कि यह "मानवीय प्रयासों" द्वारा निर्मित की जाती है, प्राकृतिक रूप में नहीं होती। इसलिए भूमि यद्यपि कृषि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बुनियादी संसाधन है परंतु भूमि को पूँजी नहीं समझा जाता है। परंतु भूमि विकास पर किये गये किसी भी निवेश को पूँजी कहा जा सकता है क्योंकि यह "मानव प्रयासों" और कृषि उत्पादन प्रक्रिया में उपयोगी "परिसंपत्ति" के मानदंड पूरा करता है। इसके अतिरिक्त पूँजी गोचर या अगोचर हो सकती है। कृषि में गोचर पूँजी का संबंध उत्पादनकारी भौतिक परिसंपत्तियों, जैसे ट्रैक्टर सिंचाई पम्प सेटों, फार्म हाउस इमारतों, गोदामों, निवेश की वस्तु-तालिकाओं आदि से है। कृषि में अगोचर पूँजी का संबंध फार्म श्रमिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण से है। वास्तव में, ऐसे पहलुओं पर व्यय से कृषि का "मानव पूँजी" का आधार बढ़ता है जो नई प्रौद्योगिकियाँ और फार्म प्रबंधन पद्धतियाँ अपनाकर उनकी उत्पादकता बढ़ाने में किसानों की सहायता करता है।

15.2.2 पूँजी निर्माण

दूसरी ओर, पूँजी निर्माण पूँजी के स्टॉक की निर्माण प्रक्रिया है। इसे अर्थव्यवस्था की चालू आय का कुछ भाग बचाकर और उसे मशीनों, औजारों, संयंत्रों और उपकरणों, परिवहन, भंडारण और संचार सुविधाओं आदि जैसे पूँजीगत माल बनाने में निवेश कर प्राप्त किया जाता है। पूँजी स्टॉक में वृद्धि किसी परिसंपत्ति विशेष में नई निवेश की गई राशि पर निर्भर करता है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि उत्पादन में प्रयुक्त पूँजीगत परिसंपत्तियाँ समय के साथ उपभुक्त हो जाती हैं इससे उसके मूल्य में कमी आ जाती है। यह "मूल्य ह्रास" कहलाता है। इसलिए यदि पूँजी उपयुक्त की दर (मूल्य ह्रास की दर) पूँजी में किए गए अतिरिक्त निवेश की दर की अपेक्षा कम है, तब उस पूँजी का स्टॉक समय के साथ बढ़ता रहेगा। इस प्रकार के निवेश पूँजीगत परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के लिए (जो परिसंपत्तियों के कार्यक्षम जीवन और कार्य की गुणवत्ता बढ़ाता है) और/या नई परिसंपत्तियाँ खरीदने के लिए हो सकते हैं। इसलिए पूँजी निर्माण प्रत्यक्ष रूप से वित्त वर्ष के दौरान पूँजीगति परिसंपत्तियों में किये गये निवेश की राशि पर निर्भर करता है। इसलिए पूँजी और निवेश के बीच संकल्पनात्मक अंतर है। निवेश, समयावधि के दौरान (सामान्यतः वित्त वर्ष के दौरान) मापा गया प्रवाह है। दूसरी ओर, पूँजी का स्टॉक नियत समय में, सामान्यतया वित्त वर्ष के अंत में मापा गया स्टॉक है। ध्यान रहे कि पूँजी निर्माण निम्नलिखित द्वारा आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सार्थक रूप से योगदान करता है : (i) भौतिक आधारभूत संरचना निर्माण में सहायता करना; (ii) आधुनिक उत्पादन तकनीकों और विधियाँ अपनाकर सुकर बनाना; (iii) कामगारों की उत्पादक क्षमता में सुधार करना; (iv) प्राकृतिक संसाधनों का दक्ष प्रयोग करके क्षमता बढ़ाना; और (v) फार्म उत्पादन, उत्पादकता और आय को बढ़ाने वाले प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों का अंगीकरण सुकर बनाना।

15.2.3 पूँजी और पूँजी निर्माण के प्रकार

कृषि में प्रयुक्त पूँजी को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है : (i) अचल पूँजी, और (ii) कार्यशील पूँजी। **अचल पूँजी** वह पूँजी है जो एक वर्ष से अधिक समय तक बनी रहती है। इसमें फार्म मशीनों में निवेश शामिल है, जैसे ट्रैक्टर, पम्पसेट, और परिसंपत्तियाँ, जैसे नलकूप, भूमि विकास, फार्म पर अन्य निर्माण आदि। **कार्यशील पूँजी** वह पूँजी है जो एक वर्ष से कम समय तक रहती है जैसे बीजों, उर्वरकों, कामगारों की मजदूरी आदि पर व्यय। इस प्रकार कृषि में पूँजी निर्माण का मान अचल में वृद्धि से विक्रय और भंडार में परिवर्तन का समंजन कर ज्ञात किया जाता है। भंडार में उत्पादन में मध्यवर्ती आदानों के लिए सामग्रियाँ और आपूर्तियाँ और बिक्री के लिए तैयार माल (जैसे पैकेजिंग) सम्मिलित होता है।

अचल पूँजी निर्माण चालू वर्ष में अचल संपत्तियों में अर्थात् कुल परिवर्तन में से मूल्य ह्रास घटाकर आकलित होता है। अनुरक्षित की जाने वाली पूँजी के स्टॉक के अनुरक्षण के लिए उपयुक्त पूँजी (अर्थात् मूल्य ह्रास) की राशि के बराबर अतिरिक्त निवेश उसी वर्ष में किया जाना चाहिए। अचल पूँजी निर्माण को आगे सकल अचल पूँजी निर्माण (GFCF) और निवल अचल पूँजी निर्माण (NFCF) में विभाजित किया जा सकता है। GFCF में चालू वर्ष अचल पूँजी के विद्यमान स्टॉक में सभी परिवर्धनों का जोड़ होता है, जबकि NFCF का संबंध चालू वर्ष के मूल्य ह्रास के निवल GFCF से है। मूल्य ह्रास (अर्थात् अचल पूँजी की खपत (CFC)) की गणना केवल सभी अचल परिसंपत्तियों (गोचर और अगोचर) के लिए की जाती है। हाँ, निम्नलिखित के लिए अचल पूँजी की खपत (CFC) की गणना नहीं की जाती : (i) बहुमूल्य वस्तुएं जो अर्जित की गई हैं (क्योंकि उनका मूल्य वास्तविक अर्थों में कालांतर में घटने की संभावना नहीं है); (ii) पशुधन; (iii) अनुत्पादित परिसंपत्तियाँ, जैसे भूमि, खनिज या अन्य निक्षेप; (iv) चालू निर्माण कार्य; और (v) युद्ध या अन्य बड़ी प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हुई अचल संपत्ति का मूल्य।

स्वामित्व के आधार पर पूँजी को निजी और सार्वजनिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्थानीय, राज्य और केंद्रीय सरकारों के स्वामित्व की पूँजी, जैसे नगरपालिका वाहित मल लाइनें, बांध, विद्युत परियोजनाएँ, सड़कें, नहरें, गोदाम, बाजार शेड आदि सार्वजनिक पूँजी हैं। व्यक्तियों/कंपनियों के स्वामित्व की कोई भी पूँजी, जैसे फार्म मशीनरी और उपकरण को निजी पूँजी कहा जाता है। कृषि सेक्टर के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की पूँजी आवश्यक है।

15.2.4 पूँजी निर्माण के स्रोत

पूँजी निर्माण के दो स्रोत हैं : देशी और विदेशी। देशी स्रोतों में शामिल हैं (i) स्वैच्छिक और अस्वैच्छिक बचत, (ii) सार्वजनिक ऋण आदान, (iii) अप्रयुक्त संसाधनों को सक्रिय करना, और (iv) घाटे की वित्त व्यवस्था। ऐच्छिक बचत के दो मुख्य स्रोत हैं: घरेलू सेक्टर और कंपनी सेक्टर। दोनों मिलकर "सार्वजनिक सेक्टर" की तुलना में हमारी कुल बचत का लगभग 90 प्रतिशत योगदान करते हैं, सार्वजनिक सेक्टर का तीसरा स्थान है और यह कुल बचत का शेष 10

प्रतिशत का योगदान करता है। इन तीन संघटकों में से घरेलू सेक्टर की बचत का स्थान उच्चतम है (लगभग 60 प्रतिशत)। जैसाकि हम जानते हैं, देशी सेक्टर की बचत अर्थव्यवस्था में आय और संपत्ति के वितरण, प्रतिव्यक्ति आय, बचत करने की प्रवृत्ति, बैंकिंग आधारभूत संरचना की उपलब्धता, ब्याज की दर आदि पर निर्भर करती है। यह आर्थिकेतर कारकों, जैसे बच्चों की शिक्षा और शादी, स्वास्थ्य और वृद्धावस्था सुरक्षा आदि के लिए बचत पर भी निर्भर करता है। कंपनी सेक्टर का अभिप्राय गैर सरकारी निजी कंपनियाँ हैं। अनैच्छिक बचत सरकार द्वारा कराधान और अनिवार्य बचत (उदाहरणार्थ, भविष्य निधि) द्वारा जुटाई जाती है। सार्वजनिक या सरकारी ऋणों का संबंध बाँड (जैसे आधारभूत संरचना विकास बाँड) जारी कर बचत जुटाने से है। निष्क्रिय संसाधनों के सक्रियण का अभिप्राय अतिरिक्त कृषि श्रमिकों को उत्पादनकारी परिसंपत्ति निर्माण के कार्य (जैसे सड़कों, नलकूपों, नहरों, विद्यालय भवनों, आदि के निर्माण कार्य) में लगाना है। स्मरण करें कि लुईस का "श्रम की असीमित आपूर्ति सिद्धांत" इसी मत पर आधारित है। अंत में, सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था से भी पूँजी बढ़ा सकती है (जिसे सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादनकारी परिसंपत्ति निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है)।

पूँजी निर्माण के विदेशी स्रोत में शामिल हैं : (i) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI); (ii) विदेशी सरकारों से ऋण (EGBs); (iii) विदेशी वाणिज्यिक ऋण (ECBs); और (iv) अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, जैसे विश्व बैंक, आदि से विकास सहायता, NRI जमा राशि। FDI का आगमन विकासशील देशों में पूँजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। यह अंतर्वाह न केवल पूँजी की दुर्लभता कम करने में सहायक होते हैं बल्कि प्रौद्योगिकी, प्रबंधन पद्धतियाँ और प्रशिक्षित मानव संसाधन भी लाते हैं। देशी कंपनियों के कार्य निष्पादन पर उनका सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। यह विशेष रूप से सत्य है जहाँ देशी कंपनियाँ विदेशी कंपनियों से सहयोग करती हैं। EGB का संबंध आधारभूत संरचना विकास, जैसे जल तथा सफाई परियोजना सड़क, स्वास्थ्य और विद्युत परियोजनाओं आदि के लिए विदेशी संस्थाओं (जैसे विश्व बैंक) से केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय संसाधन जुटाने से है। FCB विदेशों से निजी सेक्टर ऋणादान है जिसे निवेश प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये सभी अर्थव्यवस्था का पूँजी आकार बढ़ाने में सहायक होते हैं।

बोध प्रश्न 1

लगभग 50 शब्दों में उत्तर दीजिए।

1) पूँजी के गोचर और अगोचर रूपों की अवधारणा के बीच अंतर बताइए।

.....

.....

.....

.....

2) पूँजी और निवेश के बीच अंतर बताइए। किस तरीके में "पूँजी निर्माण" से निवेश संबद्ध किया जाता है?

- 3) पांच भिन्न-भिन्न तरीके बताइए जिसमें "पूँजी निर्माण" आर्थिक विकास में सहायता करते हैं।

- 4) अचल संपत्ति और कार्यशील पूँजी के बीच अंतर बताइए।

- 5) "मूल्य ह्रास" केवल अचल परिसंपत्तियों पर क्यों परिकलित किया जाता है?

- 6) कृषि में पूँजी निर्माण के दो मुख्य स्रोत क्या हैं? उनमें से कौन-सा एक देशी कंपनियों के कार्य-निष्पादन के सुधार में सहायक हो सकता है?

15.3 पूँजी निर्माण के लिए लेखाकरण की प्रणाली

भारत में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO) के वार्षिक प्रकाशन **राष्ट्रीय लेखा आँकड़े (NAS)** में कृषि सहित सभी औद्योगिक सेक्टरों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। CSO राष्ट्रीय लेखा पर प्रायः संयुक्त राष्ट्र प्रणाली (UN-SNA) के दिशा-निर्देशों का अनुसरण करता

है, जो आवधिक रूप से SNA का संशोधन तथा सुधार करता रहता है। हाल ही में UN ने SNA-2008 की संस्तुति की है। CSO के चालू अनुमानों में (नया आधार वर्ष 2004-05 है) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार SNA-2008 की संस्तुतियों का समावेश किया गया है। ये संस्तुतियाँ सार्वजनिक सेक्टर में R&D व्यय पूँजीगत व्यय के रूप में मानने, अचल पूँजी और पूँजी स्टॉक आदि की खपत का आकलन करने में परिसंपत्तियों का ह्रासमान शेष विधि अपनाने से संबंधित है।

NAS में राष्ट्रीय लेखों का अनुमान लगाने के लिए अर्थव्यवस्था को नौ उप-सेक्टरों में विभाजित किया गया है, अर्थात् (i) कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन; (ii) खनन और खदान; (iii) विनिर्माण; (iv) विद्युत, गैस और जल आपूर्ति; (v) निर्माण कार्य; (vi) व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट; (vii) परिवहन, भंडारण और संचार; (viii) वित्त, बीमा, भूमि-भवन और व्यापारिक सेवाएँ; और (ix) सामुदायिक, सामाजिक और कार्मिक सेवाएँ।

इन उप-सेक्टरों की पूँजीगत परिसंपत्तियों का मूल्यांकन बाजार कीमतों (चालू और स्थिर दोनों) पर किया जाता है। खासतौर से, सकल अचल पूँजी निर्माण (GFCF) के अनुमान तीन संस्थागत सेक्टरों में से प्रत्येक अर्थात् सार्वजनिक सेक्टर, निजी कंपनी सेक्टर और पारिवारिक सेक्टर के लिए अलग-अलग तैयार किए जाते हैं। पारिवारिक सेक्टर में GFCF के अनुमान भिन्न-भिन्न NSSO सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों से लगाए जाते हैं। फिर इनका सकल उत्पाद मूल्य या वर्धित मूल्य में अनुमानित के आधार पर प्रेक्षण किया जाता है। सार्वजनिक सेक्टर GFCF के अनुमान वार्षिक बजट प्रलेखों पर आधारित होते हैं। निजी कंपनी सेक्टर GFCF पर आंकड़े RBI द्वारा मुहैया किए जाते हैं।

कृषि में सार्वजनिक सेक्टर GFCF मुख्यतया विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा प्रारंभ किए गए प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के कारण है। लघु कार्यों, जैसे लघु सिंचाई, बागवानी, पशुपालन और सरकारी फार्मों के विकास का योगदान गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का उत्तरदायित्व होता है। लेखाकरण प्रयोजनों के लिए कृषि मंत्रालय ग्राम विकास, आदि द्वारा सस्य पालन, मृदा और जल संरक्षण, वन्य जीव, संरक्षण और अन्य कृषि कार्यक्रमों (गोचर और अगोचर परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय लोक प्रशासन (और कृषि नहीं) में पूँजी निर्माण के रूप में किया जाता है। पादपरोपण कार्यों के कारण निजी कंपनी सेक्टर में पूँजी निर्माण का अनुमान चाय, काफी और रबर बोर्डों से आंकड़े एकत्र कर लगाया जाता है।

पारिवारिक सेक्टर में पूँजी निर्माण कुएं/नलकूप खोदने, पुश्तों/संघों और फार्म हाउसों के निर्माण आदि जैसे निर्माण कार्यों से होता है। इनका अनुमान दस वर्षों में एक बार अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (AIDIS) के परिणामों का प्रयोग कर लगाया जाता है। सर्वेक्षण पश्च वर्षों के लिए अनुमान विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए अभिकलित ग्रामीण निर्माण कार्य और कृषि उत्पादन के सूचकांकों का प्रयोग करते हुए आधार वर्ष के परिणामों के प्रेक्षण द्वारा किया जाता है। कृषि मशीनरी और परिवहन उपकरणों के अनुमान वार्षिक उद्योग सर्वेक्षणों के परिणामों का प्रयोग कर AIDIS परिणामों के बहिर्निवेशन से किया जाता है। पशुधन में वृद्धि का अनुमान पंचवर्षीय पशुधन गणना के परिणामों से

बहिर्निवेशन द्वारा किया जाता है। चूँकि अधिकांश वन सरकार के स्वामित्व में हैं, वानिकी के लिए पूँजी निर्माण के अनुमान बजट प्रलेखों से संकलित किए जाते हैं। मत्स्य पालन कार्यों के लिए GFCE का अनुमान भारतीय पशुधन गणना (ILC) के परिणामों का उपयोग करके यंत्रचालित और सामान्य मत्स्य ग्रहण नौकाओं के पूँजी स्टॉक में निवल परिवर्धन के रूप में किया जाता है। एक बार पुनः गणना वर्ष पूर्व और पश्च के लिए परिणामों का बहिर्निवेशन किया जाता है।

15.3.1 कृषि में और कृषि के लिए पूँजी निर्माण

हाल ही में, कृषि में और कृषि के लिए पूँजी निर्माण के बीच विभेद किया गया है। यह विशेष रूप में इस राय के कारण है कि कुछ उद्योगों/कार्यों में पूँजी निर्माण फार्म सेक्टर को भी लाभ पहुंचाते हैं और इसलिए इस किस्म के पूँजी निर्माण का कुछ भाग कृषि के लिए भी होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रो. बी. बी. भट्टाचार्य की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट (2004) में सभी उन कार्यों को शामिल करते हुए कृषि पूँजी निर्माण के क्षेत्र का विस्तार किया जिसमें कृषि क्षेत्र को अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने में सहायता की।

तालिका 15.1 : कृषि के लिए GFCE के सेक्टरवार अनुमान

सेक्टर	कृषि, आदि	कृषि मशीनरी	उर्वरक और कीटनाशक	बिजली, गैस और जल आपूर्ति	निर्माण कार्य	व्यापार	रेलवे	भंडारण	संचार	बैंकिंग और बीमा
(GFCE) का अनुमान	1.00	1.0	0.9616	0.0855	0.088	0.245	0.066	0.693	0.091	0.0525

स्रोत : कृषि में पूँजी निर्माण समिति की रिपोर्ट, कृषि मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, 2003।

कृषि पूँजी निर्माण को दो श्रेणियों, अर्थात् कृषि में पूँजी निर्माण और कृषि के लिए पूँजी निर्माण में वर्गीकृत करते हुए समिति ने बहुत से ऐसे उद्योगों के पूँजी निर्माण के अनुपात का आकलन किया, जिसे कृषि के लिए 'GFCE' के रूप में लिया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए समझे गए उद्योग हैं : (i) उर्वरक और कीटनाशक, (ii) विद्युत्/गैस/जल आपूर्ति, (iii) निर्माण कार्य, (iv) व्यापार, (v) रेलवे, (vi) भंडारण, (vii) संचार और बैंकिंग तथा बीमा। तालिका 15.1 में इस संबंध में कृषि से GFCE का अनुमानित अनुपात दर्शाता है। कृषि और कृषि मशीनरी सेक्टर के लिए यह अनुपात 1.0 (अर्थात् 100 प्रतिशत), उर्वरक और कीटनाशक के लिए यह 0.96 (अर्थात् 96 प्रतिशत) पर सबसे अधिक था। अन्य सेक्टरों के लिए उनके मूल्य के अवरोही क्रम में संस्तुत अनुपात हैं : भंडारण (69.3 प्रतिशत), व्यापार (24.5 प्रतिशत) संचार (9.1 प्रतिशत), निर्माण कार्य (8.8 प्रतिशत), विद्युत (8.6 प्रतिशत) और बैंकिंग तथा बीमा (5.3 प्रतिशत)। इस प्रकार अन्य सेक्टरों में पूँजी निर्माण से कृषि का GFCE के परिवर्धन की सुझाई गई विधि कृषि सेक्टर के लिए GFCE का अधिक यथार्थवादी अनुमान दे सकती है।

15.4 कृषि में पूँजी निर्माण की भूमिका

पूँजी और श्रम उत्पादन के दो महत्वपूर्ण कारक हैं। ये कुछ सीमा तक प्रतिस्थापी है और काफी हद तक एक-दूसरे के पूरक हैं। कृषि के विभिन्न कार्यों के समय रहते लागत प्रभावी ढंग से संपादन के लिए अचल एवं कार्यशील पूँजी की आवश्यकता रहती है। यह सस्य सघनता बढ़ाने, सस्य क्रम परिवर्तन करने और फसल कटाई पूर्व और पश्च क्षतियां कम करने के तरीके से कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। संक्षेप में, कृषि में पूँजी निर्माण, तकनीकी प्रगति लाकर उत्पादन वक्र को ऊर्ध्वमुखी बनाने के लिए सहायक है। यह कई लाभ प्रदान कर सकता है, जैसे (i) उपज में वृद्धि, (ii) फार्म क्रियाओं का समय पर समापन, (iii) अधिकतम संभव भूमि उपयोग, (iv) फसल क्रम में अंतरण और (v) कृषि का विविधीकरण। इस प्रकार पूँजी निर्माण कृषि बाजार का विस्तार करना आसान बनाता है और इन लाभों के परिणाम में बिक्री योग्य अधिशेष में वृद्धि होती है। इस प्रकार बाजार विस्तार न केवल फार्म आय बढ़ाता है बल्कि उपभोक्ताओं को कृषि उत्पादों की सुलभता भी आसान बनाता है। इसी प्रक्रिया में यह बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा और कृषि आधारित उद्योगों के कच्चे माल की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। पूँजी निर्माण बेहतर भंडारण और परिवहन सुविधाओं के माध्यम से कृषि उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने में भी सहायक होता है। इसके फलस्वरूप यह कृषि निर्यात की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। भारत विश्व बाजार में फार्म उत्पादों के लिए प्रमुख भूमिका निभा सकता है। सेक्टर की वृद्धि के लिए योगदान करने में GFCF की भूमिका सामान्य रूप में पूँजी की किस्में सार्वजनिक तथा निजी पूँजियों के बीच विद्यमान प्रतिपूरकता के आधार पर अधिक स्पष्ट की जा सकती है।

अचल पूँजी और कार्यशील पूँजी : अचल पूँजी के अंतर्गत निम्नलिखित पर किया गया निवेश आता है: मशीनें, औजार, फार्म बिल्डिंग, ट्रैक्टर, भूमि समतलन, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, कुंआ/नलकूप, सिंचाई संरचनाएँ, वृक्ष बागान, पशुधन, भूमि विकास, मृदा और जल संरक्षण, फसल कटाई संरचना आदि। ये ऐसी निर्मित परिसंपत्तियाँ हैं जो फार्म उत्पादन, उत्पादकता और आय बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं। इसी प्रकार कार्यशील पूँजी विभिन्न फार्म निवेशों को खरीदने में सहायक होती है, जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, जल, कृषि श्रमिकों की मजदूरी, मशीनों और जुताई शक्ति का किराया। इन निवेशों और संसाधनों की आसान सुलभता विभिन्न कृषि कार्यों के समय पर निष्पादन के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, अचल और कार्यशील पूँजी की सुलभता के बिना कृषि करना व्यावहारिक नहीं हो सकता है।

सार्वजनिक पूँजी और निजी पूँजी : कृषि में पूँजी निर्माण की भूमिका के आकलन में पूँजी निर्माण को सार्वजनिक और निजी के वर्गों में विभाजित करना उपयोगी होगा। सार्वजनिक क्षेत्र पूँजी निर्माण के अंतर्गत विभिन्न गोचर और अगोचर परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा किया निवेश आता है। यह निम्नलिखित तरीके द्वारा हो सकता है : (i) भूमि विकास, (ii) छोटी और बड़ी सिंचाई परियोजनाएँ, (iii) मृदा और जल संरक्षण और जल संचयन कार्य, (iv) वनीकरण, ग्रामीण सड़कों का निर्माण और ग्रामों का विद्युतीकरण, (v) कृषि अनुसंधान और विकास, किसानों का प्रशिक्षण और क्षमता

निर्माण आदि। आप देख सकते हैं कि ये सभी निवेश/परिसंपत्तियाँ ऐसे स्वरूप और स्तर/परिमाण की हैं जिन्हें केवल सार्वजनिक निवेश द्वारा ही निर्मित किया जा सकता है। इनका स्वरूप "अवर्जनीय सार्वजनिक माल" जैसा है जिनके लिए केवल एक तर्क दिया जा सकता है कि केवल राज्य से ही यह भूमिका निभाने की आशा की जा सकती है। दूसरी ओर, निजी पूँजी किसानों द्वारा सिंचाई के लिए, जैसे कुएँ, बेध कुएँ (बोर वेल), विद्युत मोटर, डीज़ल इंजन, ट्रैक्टर और अन्य फार्म उपकरणों के लिए किया गया निवेश है। इसमें भूमि विकास, फार्म बिल्डिंग आदि पर व्यय भी शामिल है। कार्यशील पूँजी में आवश्यक आदानों की किसानों द्वारा की गई खरीद भी शामिल है। कृषि में निवेश निजी कंपनियों द्वारा भंडारण और बाजारों में निवेश के साथ-साथ फार्म मशीनों, औजारों और अन्य आदानों के विनिर्माण में किया गया निवेश शामिल है। इसलिए यह स्पष्ट है कि कृषि में सार्वजनिक और निजी दोनों निवेश कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।

सार्वजनिक और निजी पूँजी के बीच पूरकता : कृषि में सार्वजनिक और निजी निवेश पूरक और प्रतिस्थायी दोनों हैं। ऐसे कई दृष्टांत हैं, जहाँ कृषि में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप निजी निवेश भी बढ़ा हो। उदाहरण के लिए, यह देखा गया है कि सिंचाई, सड़कों और विद्युत परियोजनाओं में सरकार निवेश से कृषि में निजी निवेश प्रेरित हुआ है। दूसरे शब्दों में, यदि सरकार द्वारा बुनियादी आधारभूत संरचना निर्मित की जाती है, किसान, ट्रैक्टर और पम्प सेट खरीदने तथा नहर के कमांड क्षेत्रों में नलकूप लगाने के लिए अपनी निजी पूँजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे स्पष्ट होता है कि कृषि में अलग-अलग किसानों द्वारा अभिप्रेरित निवेश के तरीके में पूरक प्रभाव देखा गया है। दूसरी ओर, सार्वजनिक निवेश को कृषि में निजी निवेश के प्रतिस्थायी के रूप में भी माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार गहरा नलकूप, विशेषकर पृष्ठीय सिंचाई संपूरित करने और कृषि के लिए सिंचाई जल की आश्वस्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयोजन से नहर कमांड क्षेत्र में लगाती है, तो किसानों को भौम जल सिंचाई में अपना निवेश करना आवश्यक नहीं होगा। साधारणतया किसान अचल और कार्यशील पूँजी में निवेश करते हैं (जहाँ वे पूर्णतः निजी अधिकार क्षेत्र में होते हैं) जबकि सार्वजनिक निवेश उस प्रकार की परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है, जो अधिकांशतः सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में होते हैं। सार्वजनिक निवेश द्वारा निर्मित परिसंपत्तियाँ उपभोक्ता प्रभार चुका कर या उसके बिना भी किसान समुदाय द्वारा प्रयुक्त हो सकती हैं। इस प्रकार के उपयोग के उदाहरण नहर सिंचाई, मृदा और जल संरक्षण संरचनाओं, कृषि और विस्तार सेवाओं, ग्रामीण सड़कों, विद्युत आदि में देखे जा सकते हैं। कुछ अध्ययनों ने आकलित किया है कि सिंचाई और विद्युत में सार्वजनिक निवेश के लिए निजी निवेश की नम्यता लगभग 0.15 प्रतिशत है। इस प्रकार, सार्वजनिक निवेश में वृद्धि का निजी निवेश पर सकारात्मक प्रभाव होता है परंतु ऐसी स्थितियाँ भी हो सकती हैं जब सार्वजनिक निवेश में कमी की प्रतिपूर्ति करते हुए निजी निवेश में वृद्धि हो सकती है। परंतु ऐसी स्थितियाँ सामुदायिक हित में होने की संभावना नहीं हैं ये तो निजी स्वार्थ की पूर्ति के निर्मित ही हो सकती हैं। दूसरे शब्दों में, निजी निवेश पर बढ़ते हुए या घटते हुए सार्वजनिक निवेश के प्रभाव में विषमता एक वास्तविकता है। सार्वजनिक निवेश

नए बीजों, प्रौद्योगिकी, निवेशों, कृषि सेवाएँ और कृषि बाजारों के विकास के वृहत्तर प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यद्यपि किसानों को नई प्रौद्योगिकी और निवेश की सुलभता भी निजी कृषि व्यापारिक कंपनियों और आदान व्यापारियों द्वारा प्रदान की जाती है (जैसाकि संविदा खेती के मामले में होता है), परंतु व्यापार स्तर पर जिस अधिक बड़े प्रयोजन के सार्वजनिक निवेश उत्पन्न करता है उसका प्रतिस्थापन नहीं हो सकता।

15.5 पूँजी निर्माण पर संस्थागत ऋण की सुलभता का प्रभाव

ऋण सुविधाओं की सुलभता कृषि में निजी पूँजी निर्माण के प्रमुख निर्धारकों में एक है। किसानों की ऋण आवश्यकताएँ संस्थागत और गैर-संस्थागत स्रोतों से पूरी होती हैं। ऋण के गैर-संस्थागत स्रोतों के अंतर्गत साहूकारों, आदान व्यापारियों, रिश्तेदारों आदि से किसानों द्वारा लिखा गया ऋण आता है। संस्थागत ऋण के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और सहकारी ऋण समितियों से लिया गया ऋण शामिल है। अधिकांश किसानों को संस्थागत ऋणों की सुलभता प्राप्त नहीं है और इसलिए वे अधिकांशतः गैर संस्थागत स्रोतों पर निर्भर रहते हैं जो उससे 36-60 प्रतिशत प्रति वर्ष तक ऊँची ब्याज दर वसूलते हैं। परिणामस्वरूप अधिकांश किसान ऋण के जाल में फँस जाते हैं और उससे निकल पाना उनके लिए कठिन हो जाता है। अंत में, उनकी स्थिति से बाजार की अनिश्चित प्रवृत्तियाँ जुड़ जाती हैं। यही किसानों की आत्महत्याओं का मुख्य कारण बन जाता है। यद्यपि कृषि प्राथमिकता सेक्टर में है और कुल संस्थागत ऋण प्रवाह का 18 प्रतिशत इसके लिए नियत किया गया है। परंतु इस स्तर तक इस सेक्टर का ऋण नहीं पहुंचा है। किसानों की अनभिज्ञता, जटिल प्रक्रियाओं और बैंक अधिकारियों का व्यवहार बहुधा किसानों को संस्थागत ऋण लेने से रोकता है। सामान्यतया बैंक अपेक्षाकृत उच्चतर लेन-देन और परिचालन लागत के कारण किसानों को ऋण देने से बचते हैं। भुगतान में चूक के मामले में बैंक ऋण की वसूली की प्रक्रिया इतनी कठिन और जटिल है कि यह बैंकों को किसानों को ऋण देने से बचने के रास्ते ढूँढने को ही प्रोत्साहित करती है।

ऋणों की समय अवधि के आधार पर कृषि ऋण को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। बहुत अल्पकालिक ऋण का उल्लेख "फसल ऋण" के लिए किया जाता है। ये सामान्यतया बीज, खाद, उर्वरक और कीटनाशक खरीदने के लिए या मजदूरी व्यय वहन करने के लिए दिया जाता है। इसे एक वर्ष के अंदर, विशेषकर फसल कटाई के बाद चुकाया जाता है। मध्यकालिक ऋण 1-5 वर्ष तक की अवधि के लिए दिया जाता है। यह भूमि विकास, पशु खरीदने, फार्म मशीनरी, अन्य उत्पादनकारी परिसंपत्तियों के निर्माण आदि कार्यों के लिए होता है। दीर्घकालिक ऋण अचल पूँजी निर्माण जैसे ट्रैक्टर खरीदने, नलकूप लगाने, भूमि के विकास आदि के लिए लिया जाता है। इस किस्म के ऋण 5-20 वर्ष तक की अवधियों के लिए होते हैं। NSS 2003 के 'स्थिति आकलन सर्वेक्षण' (SAS) के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर किसानों के बकाया ऋण का 58 प्रतिशत

संस्थागत स्रोत से था और शेष गैर-संस्थागत स्रोत से था। इसके अलावा कुल बकाया ऋण का 58.4 प्रतिशत उत्पादनकारी प्रयोजनों के लिए लिया गया था।

तालिका 15.2 दिखाती है कि अवधि 2001-11 के दौरान अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक ऋणों में प्रवृत्ति पंचवार्षिक अंतराल की है क्योंकि यह वर्ष-दर-वर्ष घटने-बढ़ने के कारण है। इसलिए कुछ समय के विलंब के साथ ही आंकड़ों पर विचार करना अधिक उपयुक्त होगा।

तालिका 15.2 : कृषि सेक्टर की संस्थागत ऋण के प्रवाह में प्रवृत्तियाँ

ऋण की श्रेणी	2000-01	2005-06	2010-11
अल्पकालिक ऋण (कुल का %)	63.1	58.4	71.4
मध्य/दीर्घकालिक ऋण (कुल का %)	36.9	41.6	28.6
कुल (%)	100.0	100.0	100.0
कुल (रुपए करोड़ में)	52827	180485 (3.4)	446779 (2.5)

स्रोत : भारतीय कृषि की स्थिति 2011-12 कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (2012)।

नोट : कोष्ठकों के आंकड़ों में यह दर्शाया गया है कि पिछली अवधि की तुलना में कितने गुना वृद्धि हुई है।

अल्पकालिक और मध्य/दीर्घकालिक अवधि की दृष्टि दो समय बिंदुओं के बीच किसानों के अल्पकालिक संस्थागत ऋण में वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि आदान और कुछ उत्पादक परिसंपत्तियाँ खरीदने के लिए ऋण पर आग्रह रहा है। मध्य/दीर्घकालिक के ऋण के भाग में तदनुरूपी गिरावट रही है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि या तो अधिक मंहगी परिसंपत्तियों की खरीद में किसानों की रुचि घटी है या दीर्घकालिक ऋण देने के लिए बैंकों की अनिच्छा बढ़ी है। मात्रा की दृष्टि से प्रदान किये गये ऋण में गिरावट हुई है। यह 2001-06 की अवधि की तुलना में 3.4 गुणा वृद्धि से 2006-11 की अवधि में घटकर 2.5 गुणा वृद्धि हुई है। यह गिरावट 2001-06 की अवधि की तुलना में पूर्ववर्ती 5 वर्षों में अपेक्षाकृत अधिक कठिन और दबाव की परिचालक हो सकती है। यह भी स्पष्ट हो रहा है कि किसानों को किसान ऋण पत्र (KCCs) जारी करके अल्पकालिक ऋण देने की सरकार की नीति किसानों की अल्पकालिक ऋण की आवश्यकताएँ पूरी करने में प्रभावकारी सिद्ध हुई है। 2010-11 में दीर्घकालिक और मध्यकालिक ऋण कृषि के लिए दिए गए कुल ऋण प्रवाह का केवल 28.6 प्रतिशत रहे। अल्पकालिक ऋण के पक्ष में कृषि ऋण के संयोजन में अंतरण का कृषि में निजी सेक्टर की अचल पूँजी निर्माण पर प्रभाव हुआ है। अधिक गंभीरता से विचार करें तो एक बात और स्पष्ट हो रही है : KCC ऋण पर ब्याज की दर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष है जो काफी कम है और समय पर ऋण वापसी पर ब्याज सहायता का भी प्रावधान है। अतः कुछ बड़े आकार के जोत वाले किसान सस्ती दर पर KCC ऋण लेकर उसे अनौपचारिक मुद्रा बाजार में अपेक्षाकृत काफी अधिक उंची दर पर जरूरतमंद लोगों को आगे उधार देने लगे हैं। ऐसी प्रवृत्ति को ऋण प्रयोजन की सख्त निगरानी द्वारा रोका जाना चाहिए ताकि पूँजी निर्माण की प्रक्रिया को कोई क्षति न हो।

बोध प्रश्न 2

लगभग 50 शब्दों में उत्तर दीजिए।

1) दो उदाहरण दीजिए, पूँजी निर्माण पर CSO के चालू अनुमानों पर UN-SNA-2008 की सिफारिश कैसे अपनाई गई है?

.....
.....
.....
.....

2) तीन संस्थानिक उप-सेक्टर कौन-से हैं जिनके लिए GFCF के अनुमान NAS में अलग से प्रस्तुत किए गए हैं। ये अनुमान किन स्रोतों पर आधारित हैं?

.....
.....
.....
.....

3) कृषि में GFCF और कृषि के लिए GFCF के बीच विभेद करना क्यों आवश्यक समझा गया था? कृषि और संबद्ध क्षेत्र के अलावा वे मुख्य सेक्टर क्या हैं जिनसे GFCF का अनुपात कृषि के GFCF के लिए उत्तरदायी होने की सिफारिश की गई थी।

.....
.....
.....
.....

4) उन पाँच भिन्न-भिन्न तरीकों का उल्लेख कीजिए जिनसे पूँजी निर्माण कृषि उत्पादन वृद्धि में सहायक होता है?

.....
.....
.....
.....

5) उन कुछ तरीकों का उल्लेख कीजिए जिनमें कृषि में पूँजी निर्माण कृषि निर्यात की संभावनाएँ बढ़ा सकता है?

.....
.....

6) वे क्या कारक हैं जो गरीब किसानों को संस्थागत ऋण लेने से रोकते हैं? वे कारण भी बताइए जो कृषि के लिए ऋण की प्राथमिकता की सरकार की नीति के बावजूद बैंकों को किसानों को ऋण देने से हतोत्साहित करते हैं।

7) किस किस के संस्थागत ऋण ने पिछले एक दशाब्दी में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई है? कृषि सेक्टर की पूँजी निर्माण के लिए इसके क्या प्रभाव हुए हैं?

15.6 सकल पूँजी निर्माण में प्रवृत्तियाँ

अर्थव्यवस्था के कुछ GCF के प्रतिशत के रूप में कृषि में सकल पूँजी निर्माण (GCFA) 1979-80 में 20.2 प्रतिशत था। यह अब बहुत तेज़ी से गिरकर 2009-10 में लगभग 7.7 प्रतिशत रह गया है। यह सार्वजनिक/निजी सेक्टर विभाजन के अनुसार कृषि में सार्वजनिक सेक्टर के GFCF के अंश में भारी कमी के कारण हुआ है। यह 1981-82 में 54 प्रतिशत से 1991-92 में 24.4 प्रतिशत और आगे 2001-02 में 14.3 प्रतिशत नीचे आ गया है। यह दर्शाता है कि 1980 की दशाब्दी के मध्य के बाद कृषि में पूँजी निर्माण अधिकांशतः निजी क्षेत्र द्वारा संचालित रहा है, यहाँ तक कि 1990 की दशाब्दी के अंत तक निजी निवेश सेक्टर में कुल निवेश का लगभग तीन चौथाई था। परंतु अभी हाल ही के वर्षों में सार्वजनिक सेक्टर GCFA का शेयर बढ़ा है, यह 2002-03 में 14.3 प्रतिशत था जो बढ़कर 2006-07 में 26.3 प्रतिशत हुआ (यद्यपि एक बार फिर 2009-10 में गिरकर 18.5 प्रतिशत हुआ)। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र GCF में कृषि के घटते हुए शेयर से प्रकट होता है कि कृषीतर सेक्टर में पूँजी निर्माण कृषि सेक्टर की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ा है। क्योंकि समय के चलते देश के समग्र GDP में कृषि का योगदान भी बहुत अधिक घटा है। फिर भी, यदि हम कृषि GDP में उसके प्रतिशत शेयर के अनुसार GCFA का अनुमान करते हैं, तो हम देखते हैं कि कृषि GDP के प्रतिशत के रूप में GCFA समय के दौरान बढ़ा है।

15.6.1 सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पूँजी निर्माण में हास के कारण

सार्वजनिक निवेश का घटता हुआ शेयर गंभीर समस्या है क्योंकि यह न केवल कुल कारक उत्पादकता (TFP) वृद्धि बढ़ाने के लिए कृषि सेक्टर में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुछ अनुमान दिखाते हैं कि सार्वजनिक निवेश में 10 प्रतिशत हास से कृषि GDP में 2.4 प्रतिशत की कमी होती है। इसके बावजूद कृषि में सार्वजनिक निवेश की गिरावट के लिए कई कारण हैं। उनमें प्रमुख हैं (i) प्रत्यक्ष निवेश साहाय्य की ओर संसाधनों का पथांतरण; (ii) विद्यमान परियोजनाओं के अनुरक्षण की लागत में वृद्धि; (iii) परियोजना पूरी होने में विलंब; और (iv) अवरुद्ध R&D निवेश। इन सबसे अधिक, उदारीकरण पश्च, अवधि के दौरान समष्टि आर्थिक संकुचन की प्रक्रिया और परिणाम में सरकार की विकास भूमिका में कटौती फार्म सेक्टर में सार्वजनिक निवेश कम होने का मुख्य कारण है। चूंकि राजकोषीय घाटा कम करने के लिए योजनेत्तर व्यय कम करना सरकार के लिए कठिन था, इसलिए उसने 1990 के दशक के दौरान कृषि और सामाजिक, दोनों सेक्टरों में पूँजीगत व्यय कम करने का विकल्प चुना। यद्यपि, सरकार राजकोषीय घाटा नियंत्रण में लाने में सफल नहीं हो सकी, किंतु फार्म सेक्टर में उत्पादनकारी निवेश पर्याप्त रूप में कम हो ही गया। खाद्य, उर्वरक ऋण और अन्य आदानों पर बढ़ते हुए साहाय्य से कृषि में वास्तविक निवेश नहीं हुआ। इसके अलावा कृषि सब्सिडी से फसलक्रम में भी विकृति आई, संसाधन आबंटन में अदक्षता उत्पन्न हुई और कृषि धारणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

कृषि राज्य विषय है। अधिकांश राज्य राजकोषीय कुप्रबंधन और उनके द्वारा अपनाए गए लोक लुभावन उपायों के कारण गंभीर राजकोषीय सेक्टर में हैं। राज्य सरकारों की खराब राजकोषीय स्थिति का भी कृषि में वास्तविक निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कृषि और संबद्ध कार्यों पर राज्यों का संचयी व्यय (कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में) 1980-81 में 8 प्रतिशत की तुलना में 1990 के दशक के मध्य से 4-6 प्रतिशत के इर्द-गिर्द बना रहा। नौवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया गया है कि पिछली दशाब्दी में कृषि में उत्पादनकारी अचल परिसंपत्तियों और आधारभूत संरचना में निवेश के स्थान पर आदान साहाय्यों द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं।

कृषि साहाय्यों को लक्षित और कम करके तथा सिंचाई और अन्य आधारभूत संरचना संबंधी कार्यों में निवेश के रूप में कृषि सेक्टर के लिए निर्मित संसाधनों पुनः सक्रिय करके सार्वजनिक सेक्टर पूँजी निर्माण बढ़ाया जा सकता है। कृषि निवेश के लिए संसाधनों का आर्थिक रूप से वित्त पोषण सार्वजनिक सेक्टर के उपक्रमों को बेचकर किया जा सकता है। जिनका संचलन अदक्षता से ग्रस्त रहा है। इस प्रकार निम्न लागत पर सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करने में सहायता मिल सकती है। साहाय्य जनित विकृति समाप्त करने से पर्यावरण क्षति में कमी और सरकारी संसाधन जुटाने में वृद्धि भी हो सकती है।

कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र के पूँजी निर्माण में हास की प्रतिपूर्ति निजी सेक्टर द्वारा पूँजी निर्माण में वृद्धि से हुई है। किंतु निजी क्षेत्र में पूँजी निर्माण का स्वरूप सार्वजनिक पूँजी निर्माण से भिन्न है। अतः ये प्रतिपूर्ण संपूर्ण रूप से नहीं हो सकती। निजी क्षेत्र निवेश अधिकांशतः फार्म मशीनीकरण,

भूमि समतलन, भौम जल सिंचाई (जैसे बेधकूल/नलकूप) आदि में किया जाता है, जबकि सार्वजनिक निवेश दीर्घकालिक परिसंपत्तियों, जैसे, बांधों, नहरों, सड़कों, विपणन परिसरों के निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि R&D आदि के निर्माण पर किया जाता है। इस प्रकार की पूँजी निजी क्षेत्र द्वारा नहीं बनाई जाती। वास्तव में, इन किस्मों की पूँजी का निर्माण कृषि में अधिक निजी पूँजी निर्माण को प्रेरित करने के लिए अपेक्षित है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण विद्युतीकरण किसानों को विद्युत चालित नलकूप (ट्यूब वेल) लगाने को प्रेरित करता है। हम अब निजी पूँजी निर्माण के निर्धारक तत्वों पर अधिक गहनता से विचार करेंगे।

15.7 कृषि में निजी पूँजी निर्माण के निर्धारक तत्व

कृषि में निजी निवेश को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। उनमें महत्वपूर्ण हैं : (i) व्यापार की शर्तें और संस्थागत ऋण का प्रवाह; (ii) कृषि आधारभूत संरचना में सार्वजनिक निवेश; (iii) कृषि साहाय्य; (iv) प्रौद्योगिकी का प्रवाह; (v) स्वकर्षित जोतों के आकार में वृद्धि आदि। कृषि के लिए व्यापार की अनुकूल शर्तें कृषि में लाभकारिता बढ़ा सकती हैं और किसानों को GCF में अधिक व्यय करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं।

जैसाकि पहले चर्चा की गई है, सस्ती दरों पर किसानों को संस्थागत ऋण की सुलभता फार्म सेक्टर में अचल और कार्यशील दोनों पूँजी निर्माण के मुख्य निर्धारकों में एक है। सिंचाई, विद्युत, सड़क, बाजार, मृदा और जल संरक्षण, कृषि, R&D, विस्तार आदि में सार्वजनिक निवेश कृषि में निजी निवेश को प्रेरित करता है। इस दृष्टि से सार्वजनिक निवेश निजी निवेश का पूरक है। यद्यपि आमतौर पर साहाय्यों का निजी निवेश पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, किंतु ट्रैक्टरों, पम्प सेटों, उर्वरक, विद्युत, डीज़ल आदि पर कृषि साहाय्य का कृषि में निजी पूँजी निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव होता है। इसी प्रकार, यद्यपि बढ़ते हुए कृषि साहाय्य सार्वजनिक GCFA पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और संसाधन आबंटन में अदक्षता बढ़ाते हैं, ये साहाय्य किसानों को अधिक पूँजी परिसंपत्तियां खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार निजी GCFA बढ़ाती है।

प्रौद्योगिक प्रगति भी कृषि में निजी पूँजी निर्माण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। हरित क्रांति और उसके बाद से कृषि में अपनाई गई नई प्रौद्योगिकियां अधिक परंपरागत प्रौद्योगिकी की तुलना में पूँजी प्रधान रही हैं।

जोतों के विभाजन के कारण स्वकर्षित जोतों की बढ़ती हुई संख्या से GCFA बढ़ने की संभावना होती है क्योंकि जोतों के विभाजन से फार्म परिसंपत्ति और मशीनरी में निवेश के लिए मांग बढ़ती है। भारत में स्वकर्षित जोतों की संख्या 1985-86 में 97.2 मिलियन थी जो बढ़कर 2000-01 में 120.82 मिलियन हो गई। 23.66 मिलियन जोतों की वृद्धि हुई है।

फार्म सेक्टर को संस्थागत ऋण और साहाय्य की उपलब्धता इन विभाजित जोतों को फार्म मशीनरी में निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। कुछ अध्ययनों से सिद्ध किया है कि किसानों को संस्थागत ऋण और कृषि के लिए व्यापार की शर्तों का राष्ट्रीय स्तर पर निजी पूँजी निर्माण में सकारात्मक और उल्लेखनीय प्रभाव हुआ है, दो निष्कर्ष जो इन कारकों से निकाले जा सकते हैं, निम्न प्रकार हैं :

- क) चूँकि मुख्य कृषि आधारभूत संरचनाओं में सार्वजनिक निवेश का निजी पूँजी निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव होता है, सरकार को कृषि में निजी निवेश प्रोत्साहित करने के लिए सिंचाई, विद्युत, सड़क, बाजार, R&D आदि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना चाहिए।
- ख) कृषि के लिए व्यापार को शर्तें आदानों को साहाय्य देकर सुधारा जा सकता है। यह सुझाता है कि कृषि साहाय्यों को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, परंतु, इन्हें तर्कसंगत और प्रभावशील बनाया जाना चाहिए।

बोध प्रश्न 3

प्रश्न 2 से 5 के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए।

1) रिक्त स्थान भरो –

- क) कुल GCF के प्रतिशत के रूप में GCFA (कृषि में सकल पूँजी निर्माण) 1979-80 में प्रतिशत से घटकर 2009-10 में प्रतिशत हुआ।
- ख) सार्वजनिक सेक्टर का GCFA का शेयर 1981-82 में प्रतिशत से 1991-92 में प्रतिशत और 2001-02 में प्रतिशत तेज़ी से घटा है।
- ग) अभी हाल ही के वर्षों में सार्वजनिक सेक्टर का GCFA का शेयर 2002-03 में प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में प्रतिशत हुआ परंतु एक बार फिर 2009-10 में गिरकर प्रतिशत रह गया।

2) कृषि में सार्वजनिक निवेश की गिरावट के पांच महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

3) किस आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि निजी क्षेत्र का GCFA सार्वजनिक क्षेत्र के GCFA में गिरावट के लिए प्रतिपूर्तिकारी कारक नहीं हो सकता है?

.....

.....

.....

.....

4) उन पांच महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख कीजिए जो कृषि में निजी निवेश प्रभावित करते हैं।

.....

-
-
-
- 5) उन भिन्न-भिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए जो निजी क्षेत्र का GCFA निर्धारित करते हैं, अपेक्षित नीति आग्रह के विषय में दो मुख्य निष्कर्ष क्या निकाले जा सकते हैं?
-
-
-
-

15.8 सारांश

कृषि यद्यपि श्रम प्रधान कार्य है, परंतु इसे विभिन्न प्रकार्यों का दक्षतापूर्वक निष्पादन करने के लिए अचल और कार्यशील दोनों पूँजियों की आवश्यकता भी होती है। पूँजी में वे परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जो उत्पादित की जाती है (जो गोचर और अगोचर भी हो सकती है), जिन्हें आगे माल और सेवाएँ उत्पन्न करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पूँजी निर्माण चालू आय का एक भाग बचाकर पूँजी के स्टॉक का निर्माण और पूँजीगत माल/परिसंपत्तियाँ उत्पन्न करने में काम लाया जाता है। यही निवेश करने की प्रक्रिया है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान अचल संपत्ति में से कुछ अंश की खपत हो जाती है, यह मूल्य ह्रास कहलाता है। यदि अचल परिसंपत्ति की खपत की दर परिसंपत्ति में निवेश की दर की अपेक्षा कम है तब उस अचल परिसंपत्ति का स्टॉक में वृद्धि होगी।

कृषि में पूँजी सार्वजनिक और निजी दोनों सेक्टरों द्वारा निर्मित की जाती है। सार्वजनिक सेक्टर पूँजी निर्माण में कृषि आधारभूत संरचना, जैसे लघु और बड़ी सिंचाई परियोजनाएँ, R&D और विस्तार सेवाएँ, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि में निवेश होता है। निजी पूँजी निर्माण में किसानों द्वारा फार्म मशीनों, नलकूपों, खेत की नालियों, भूमि विकास और अन्य उत्पादनकारी परिसंपत्तियाँ आदि में निवेश होता है। सार्वजनिक और निजी पूँजी निर्माण दोनों भारतीय कृषि के प्रबल विकास के लिए आवश्यक है।

1960-61 वर्ष के बाद से GCFA में प्रवृत्तियाँ दर्शाती हैं कि अर्थव्यवस्था के कुल GCF के प्रतिशत के रूप में GCFA का अंश 1980 की दशाब्दी के बाद से गिरा है। सार्वजनिक सेक्टर GCFA में गिरावट में इतनी तीव्रता थी कि कुल GCFA के लिए सार्वजनिक सेक्टर GCFA का शेयर तेजी से गिरा है, यह 1981-92 में 54 प्रतिशत से गिरा और 2001-02 में 14.3 प्रतिशत रह गया। यद्यपि 2006-07 में बढ़कर यह 26.3 प्रतिशत हो गया। फिर भी यह अभी भी गंभीर समस्या है क्योंकि निजी सेक्टर में वृद्धि निम्नतर सार्वजनिक सेक्टर GCFA के हानिकारक प्रभाव की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है। यह कृषि में सार्वजनिक

सेक्टर के गिरते हुए शेयर के कारणों की पहचान करने और कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए ठीक करने के नीतिगत उपाय लेने पर महत्वपूर्ण बल देता है।

15.9 शब्दावली

- पूँजी संचयन** : इसका संबंध किसी अवधि के दौरान पूँजी स्टाक से है जब परिसंपत्ति में मूल्य ह्रास की दर उसमें किए गए निवेश की दर की अपेक्षा कम होती है।
- गोचर पूँजी** : इसका संबंध उत्पादनकारी भौतिक परिसंपत्तियों, जैसे ट्रैक्टर, फार्महाउस, नलकूप, डीज़ल इंजन आदि, से है।
- अगोचर पूँजी** : इसमें भौतिक पदार्थ से भिन्न परिसंपत्तियाँ आती हैं जो कृषि उत्पाद में योगदान करती हैं, जैसे कामगारों की शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य आदि में निवेश।
- अचल पूँजी** : इसका संबंध उस पूँजी से है जो एक वर्ष से अधिक समय तक रहती है जैसे, फार्म बिल्डिंग, ट्रैक्टर, पम्प सेट आदि।
- कार्यशील पूँजी** : इसका संबंध उस पूँजी से है जो एक वर्ष से कम समय तक रहती है जैसे बीजों, उर्वरक आदि की खरीद पर व्यय।
- संस्थागत ऋण** : इसका संबंध उन ऋण/कर्ज से है जो वित्तीय संस्थाओं जैसे वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मुहैया किया जाता है।

15.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

Chand, Ramesh (2000), *Emerging Trends and Regional Variations in Agricultural Investments and their implications for Growth and Equity*, Policy Paper, National Centre for Agricultural Economics and Policy Research, New Delhi.

Govt. of India (2012), *State of Indian Agriculture 2011-2012*, Ministry of Agriculture and Cooperation, New Delhi.

Gulati, A and Bathla, S. (2002), *Capital Formation in Indian Agriculture : Trends, Composition and Implications for Growth*, Occasional Paper 24, NABARD, Mumbai.

15.11 बोध प्रश्नों के उत्तर/संकेत

बोध प्रश्न 1

- 1) देखिए उपभाग 15.2.1 और उत्तर दीजिए।
- 2) देखिए उपभाग 15.2.1 और उत्तर दीजिए।
- 3) देखिए उपभाग 15.2.2 और उत्तर दीजिए।
- 4) देखिए उपभाग 15.2.3 और उत्तर दीजिए।
- 5) देखिए उपभाग 15.2.3 और उत्तर दीजिए।
- 6) देखिए उपभाग 15.2.4 और उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न 2

- 1) देखिए भाग 15.3 और उत्तर दीजिए।
- 2) देखिए भाग 15.3 और उत्तर दीजिए।
- 3) देखिए उपभाग 15.3.1 और उत्तर दीजिए।
- 4) देखिए भाग 15.4 और उत्तर दीजिए।
- 5) देखिए भाग 15.4 और उत्तर दीजिए।
- 6) देखिए भाग 15.5 और उत्तर दीजिए।
- 7) देखिए भाग 15.5 और उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न 3

- 1) क) देखिए भाग 15.6 और उत्तर दीजिए।
ख) देखिए भाग 15.6 और उत्तर दीजिए।
ग) देखिए भाग 15.6 और उत्तर दीजिए।
- 2) देखिए उपभाग 15.6.1 और उत्तर दीजिए।
- 3) देखिए उपभाग 15.6.1 और उत्तर दीजिए।
- 4) देखिए भाग 15.7 और उत्तर दीजिए।
- 5) देखिए भाग 15.7 और उत्तर दीजिए।